1991-92	60	46	45	151	278546	5136
1992-93	57	29	45	131	251665	2310

उपर्युक्त अन्वेषण कार्य निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में शुरू किया गया—जैसे रानीगंज, झरिया, राजमहल, नार्थ करनपुरा, साउथ करनपुरा, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, रामगढ़, पाठाखेरा, काम्पटी, वर्धा वैली, बंडर, पेंच कान्हा, कोरबा, सोहागपुर, मंड रायगढ़, विश्रामपुर, उमरिया, सेंदुरगढ़, हसदेव-अरंड, लखनपुर, जोड़िला, सोनहट, सिंगरौली, तालचर, इब और माकुम, इत्यादि ।

(घ) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान अन्वेषण अधीन 131 अन्वेषित ब्लाकों में से केवल 29 ब्लाक ओपनकास्ट प्रत्याशित, जबकि 57 ब्लाक भूमिगत प्रत्याशित थे और 45 ब्लाक उत्पादन समर्थन अपेक्षाओं के लिए शुरू किए गए थे ताकि विद्यमान भूमिगत खानों से उत्पादन को बढ़ाया जा सके ।

कोयला धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण में विलम्ब

2448. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण के कार्य में देरी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो 1987 के पश्चात कितनी धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण के कार्य में देरी की गयी;

(ग) आधुनिकीकरण के कार्य में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) 10 विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों के आधुनिकीकरण का कार्य (6 भारत कोकिंग कोल लि० और 4 सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०) सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अंतर्गत शुरू किया गया था । आधुनिकीकरण को पूरा किए जाने का कार्य "लघु-अवधि" एवं "दीर्घ-अवधि" उपायों से संबद्ध है, जिसकी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी । लघु-अवधि तथा दीर्घ-अवधि उपायों के क्रियान्वयन को दो वाशरियों में पूरा कर लिया गया है अर्थात भारत कोकिंग कोल लि० की मूनीडीह और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० की स्वांग वाशरियों में । लघु-अवधि और दीर्घ-अवधि उपायों के क्रियान्वयन को दो वाशरियों को पूरा कर लिया गया है । शेष वाशरियों में दीर्घ-अवधि उपायों के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है । विलंब का कारण मुख्यत: कोयला कंपनियों के पास वित्तीय स्रोतों की कमी थी ।

भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन

2449. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला कंपनियों के दुलमुल रवैये के कारण भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन स्थिर बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष कितना-कितना रहा; और

(ग) सरकार भूमिगत खानों और खुली खानों से उत्पादन के लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिछले 5 वर्षों से भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों के संबंध में कोयला उत्पादन के लक्ष्य अलग से निर्धारित किए जा रहे हैं ।

कोयला परियोजनाओं की लागत में अन्तर

2450. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय मुद्रास्फीति पर ध्यान नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजनाओं की लागत में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) जी, हां । विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार कोयला परियोजनाओं के लागत अनुमानों को "चालू कीमतों" के आधार पर निर्धारित किया जाता है और अनुमानों में मुद्रास्फीति के कारण लागत में हुई वृद्धि के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी जाती है । परियोजना निर्माण अवधि के दौरान आमतौर पर लागत में, बाजार मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में वृद्धि होने, करों तथा शुल्कों में परिवर्तन होने और